to Questions

चला है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसकी क्या स्थिति है और वह कब तक चल जाएगा?

جناب جاوید علی خان : مانئے سبھا پتی جی، ابھی 24 مئی کو سنسد سدسئیوں کے رزرویشن کے لئے آئی۔آرسی ٹیسی۔ کی طرف سے ایک یوزر آئی ڈی۔ اور پاس۔ورڈ جاری کیا گیا تھا، لیکن وہ آج تک نہیں چلا ہے۔ میں مانئے منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا استتھی ہے اور وہ کب تک چل جائے گا؟

SHRI ANGADI SURESH CHANNABASAPPA: Sir, the hon. Member has taken interest in raising this issue. But, I wish to submit, though it does not fall within the purview of the main question, that I will make inquiry with the concerned officials and send him a detailed reply.

राजस्थान में प्रस्तावित रेल परियोजनाएं

*12. श्री राम नारायण डूडी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय राजस्थान के लिए कुछ महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं जैसे, पूर्व में यथा प्रस्तावित पीपाड़ रोड रेलवे स्टेशन से वाया भोपालगढ़ आसोप से होते हुए नागौर, पूर्व में यथाप्रस्तावित बिलाड़ा से बर रेल लाइन और मेडता रोड़ से वाया मेड़ता शहर और पुष्कर होते हुए अजमेर तक नई रेल लाइनों पर विचार कर रहा है या इस संबंध में कोई प्रस्ताव किया है;

- (ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अंगादि सुरेश चन्नाबासप्पा): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी हां। रेल मंत्रालय ने 2014-15 से 12 नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल की हैं, जो अंशत:/पूर्णत: राजस्थान राज्य में पड़ती हैं। इस समय, 42820 करोड़ रु. की लागत वाली 11 नई लाइन, 06 आमान परिवर्तन और 13 दोहरीकरण परियोजनाएं निष्पादन/स्वीकृति के विभिन्न चरणों में हैं।

(i) भोपालगढ़, आसोप के रास्ते पीपाड़ रोड रेलवे स्टेशन से नागौर तक नई रेल लाइन (96 कि.मी.): पीपाड़ रोड़-भोपालगढ़-शंकवास-नागौर तक नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण 2014-15 में पूरा किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 9.46% ऋणात्मक दर के प्रतिफल सहित इसकी लागत 293 करोड़ रुपए आंकी गई थी। परियोजना के वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद होने के कारण, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

[†]Transliteration in Urdu script.

- (ii) बिलाड़ा-बर नई लाइन (47 कि.मी.): बिलाड़ा बर नई लाइन के लिए सर्वेक्षण 2016-17 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इन नई लाइन (47 किलोमीटर) की लागत प्रतिफल की 26.93% ऋणात्मक दर के साथ 368 करोड़ रुपए थी। फिर भी, बिलाड़ा-बर तक नई लाइन के निर्माण के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण दिसम्बर 2018 में स्वीकृत किया गया है। सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
- (iii) मेड़ता सिटी और पुष्कर के रास्ते मेड़ता रोड़-अजमेर (59 कि.मी.): मेड़ता रोड़ सिटी और पुष्कर-अजमेर के बीच पहले ही रेल लाइन मौजूद है। मेड़ता सिटी से पुष्कर तक एक परियोजना 2013-14 के रेल बजट में शामिल की गई थी, बशर्ते अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त हो। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना की लागत प्रतिफल की 7.65% ऋणात्मक दर के साथ लगभग 323 करोड़ रुपए (2010-11 कीमत स्तर) थी। परियोजना के वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद होने के कारण, कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

Proposed railway projects in Rajasthan

†*12. SHRI RAM NARAIN DUDI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Ministry is considering or has proposed important railway projects for Rajasthan, namely, new railway line from Pipar Road railway station to Nagaur *via* Bhopalgarh Asop, as proposed earlier, Bilara to Bar railway line, as proposed earlier, and Merta Road to Ajmer *via* Merta City and Pushkar;

- (b) if so, by when these projects would be completed; and
- (c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI ANGADI SURESH CHANNABASAPPA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Yes, Sir. Ministry of Railways has included 12 New Line, gauge conversion and doubling projects since 2014-15 falling partly/fully in the State of Rajasthan. As on date, 11 New Lines, 06 Gauge Conversion and 13 Doubling projects worth ₹ 42,820 crore are under different stages of execution/sanction.

 (i) Pipar Road Station Nagour via Bhopalgarh, Asop new railway line (96 Km): Survey for new Broad Gauge line from Pipar Road-Bhopalgarh-Asop-Shankwas-Nagour has been completed in 2014-15. As per survey report, the

[†]Original notice of the question was received in Hindi.

cost was assessed as ₹293 crore with the negative rate of return of 9.46%. Project could not be taken forward as the project is financially unviable.

- (ii) Bilara-Bar new line (47 km): Survey for Bilara-Bar new line was completed in 2016-17. As per survey report, cost of (47 km.) new line was ₹368 crore with negative rate of return of 26.93%. However, an updating survey for construction of new line from Bilara-Bar has been sanctioned in December, 2018. Survey taken up.
- (iii) Merta Road-Ajmer *via* Merta City and Pushkar (59 km): Railway line already exists between Merta Road-Merta City and Pushkar-Ajmer. The project for Merta City to Pushkar was included in Railway Budget 2013-14 subject to requisite approvals. As per survey report, the cost of the project was approx ₹323 crore (2010-11 price level) with negative rate of return of 7.65%. Project could not be taken forward as it is financially unviable.

श्री राम नारायण डूडी: सभापति महोदय, मैंने जोधपुर, नागौर और अजमेर से संबंधित रेल लाइन के संबंध में प्रश्न पूछा है। सर, बिलाड़ा से बर रेलवे लाइन का जो मसला है, यह बहुत पुराना मसला है। जब मैं 1977 में राजस्थान के अंदर एम.एल.ए. बना, तब इसकी शुरूआत हुई थी ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप अभी वहां तक मत जाइए। ...(व्यवधान)...

श्री राम नारायण डूडी: सभापति महोदय, मैं supplementary प्रश्न पर आ रहा हूं। मैं इसके background के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 1977 यानी उससे पहले भी मारवाड़ के अंदर बिलाड़ा और बिलाड़ा से दक्षिण के लिए हमेशा आना-जाना रहता था। सभापति महोदय, कितने साल हो गए feasibility बदल गई, हजारों टोला भट्टे आ गए, हजारों ट्रक्स हो गए और हजारों लोगों का जो प्रवासी राजस्थानी हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपका Question क्या है?

श्री राम नारायण डूडी: सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह रेलवे लाइन कब पूरी कर दी जाएगा? केवल feasibility की बात करने से काम नहीं चलेगा। यह केवल 300 करोड़ रुपये का मामला है। मैंने जो प्रश्न पूछा है उसके अंदर 1000 करोड़ रुपये तक सारे के सारे जनहित के मामले हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका जवाब दें।

SHRI ANGADI SURESH CHANNABASAPPA: Sir, it is only the Narendra Modi Government which has given the maximum sanctions to the State of Rajasthan. There are more than 12 projects under implementation. Other than this, more than ₹2.98 lakh crores worth of projects are in the pipeline. What we have given is the present day cost. But, if you look at the actual cost, it is much more. The work is under progress. Once these works are completed, the projects can be utilized for the people of Rajasthan. After completing these projects, the remaining proposals will be examined.

श्री हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर: सभापति जी, मैं रेल मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि(व्यवधान)...

श्री राम नारायण डूडी: सभापति महोदय, मेरा second supplementary प्रश्न नहीं हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपका second supplementary प्रश्न आएगा। ...(व्यवधान)... डूडी जी, मैं आपको बुलाऊंगा। थोड़ी तेजी से गाड़ी आगे बढ़ गई है। मैं आपको अभी बुलाऊंगा।

श्री हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर: सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अहमदाबाद और उदयपुर के बीच में जो कन्वर्ज़न हो रहा है, तो डूंगरपुर में डुंगरपुर और बिच्छीबाड़ा के बीच रेलवे ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज क्यों नहीं बन रहा है और यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा?

SHRI ANGADI SURESH CHANNABASAPPA: I appreciate the interest shown by the hon. Member. But, his supplementary does not fall within the purview of the main question. I will get a detailed report and send it to the hon. Member.

श्री सभापतिः श्री राम नारायण डूडी, second supplementary.

श्री राम नारायण डूडी: सभापति महोदय, एक तो मैंने मेड़ता रोड़ से अजमेर या पुष्कर के बारे में पूछा है। यह जो पुष्कर है, यह हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा दूसरा तीर्थ है। यहां पर हमेशा हजारों की तादाद में लोग आते-जाते हैं। ब्रह्मा जी का केवल एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। हिंदुओं का महान तीर्थ होते हुए भी उसको सीधे मारवाड़ से जोड़ा नहीं गया है। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि इस संबंध में रेल मंत्री महोदय कुछ आश्वासन दें।

श्री पीयूष गोयलः मैं माननीय सांसद जी के प्रस्ताव के प्रति पूरी तरह से संवेदना रखता हूं। वास्तव में पुष्कर हम सभी के लिए बहुत ही अहम स्थान है और हम सभी की इच्छा होती है कि हम वहां जाएं और आप हम सबको भी वहां बुलाएं और इतनी सुंदर जगह का स्वाद ले सकें, लेकिन रेलवे की अपनी कुछ समस्याएं हैं। रेलवे में पिछले वर्ष 2018-19 में साढ़े चार हजार करोड़ रुपये, जो इतिहास में सबसे ज्यादा राशि है, मात्र राजस्थान के प्रोजेक्ट्स को मिली है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: यह ठीक है, लेकिन उनकी मांग क्या है?

श्री पीयूष गोयल: सभापति महोदय, जहां तक एक-एक individual line है, यह पुराने जमाने में एक बीमारी रेलवे को मिली है कि लोग माननीय सांसद को खुश करने के लिए दना-दन प्रोजेक्ट्स sanction कर देते थे। लेकिन पैसा रहता नहीं था, प्रोजेक्ट्स खत्म नहीं होते थे, प्रोजेक्ट्स कॉस्ट बढ़ती जाती थी, इसकी वजह से सरकार ने बहुत ही अक्लमंदी से यह निर्णय लिया कि पहले पुराने प्रोजेक्ट्स को खत्म करें और लोगों की अच्छी तरह से सेवा करें और फिर नये प्रोजेक्ट्स को शुरू करें। MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. Unfortunately, two more questions have still been left out.

The House is adjourned till 2.30 p.m.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Stock of onions in the country

*13. SHRI D. KUPENDRA REDDY: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the Central Government has assessed the stock position of onions in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any shortfall in production of onions or its supply in the market is expected in the coming months; and

(d) if so, the details thereof and reasons therefor along with the steps taken/being taken by the Central Government in this regard?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) and (b) As per the estimates of Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, the storage of onion in the year 2017 and 2018 were 48.73 lakh MT and 50.03 lakh MT, respectively.

(c) and (d) As per 2nd Advance Estimates (2018-19) released by Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, production of Onion is estimated to be 232.84 lakh Tonne in 2018-19 which is marginally higher than estimated production of 232.62 lakh Tonne in 2017-18.

During the year 2019-20, as on 17.06.19, buffer of around 44,812 MT of onions has been built under Price Stabilization Fund (PSF) for calibrated release during the lean season for moderating prices. The Central Government has offered onions from the buffer to States/ UTs at no profit no loss basis to improve availability and moderate prices of onions during lean season. In addition, incentive on exports of onions under Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) has been withdrawn since 11th June 2019 to improve domestic availability and moderate prices.